(ख) जिन प्रकाशन संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे, उनके नाम तथा पते नीचे दिये गए हैं :—

—हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप,

—फ्री प्रेस जर्नल,

—टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिशर्स,

—थॉमसन प्रैस,

— आनन्द बाज़ार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स

परन्तु, इनसे प्राप्त हुए उत्तर उत्साहवर्धक नहीं थे तथा इनमें से कुछ तो "बिना लाभ-हानि" के आधार पर पत्रिका का प्रकाशन करने के इच्छुक नहीं थे । इसी बीच, मैसर्ज़ मीडिया ट्रांसेशिया (थाईलैंड) लिमिटेड, बैंकाक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे उपयुक्त पाया गया तथा प्रकाशन का कार्य विदेश की इस फर्म को सौंप दिया गया ।

(ग) समझौते के अनुसार, इंडियन एयरलाइंस को हर तीन माह के पश्चात् उड़ानगत पत्रिका, "स्वागत" की 50,000 प्रतियां सप्लाई की जाएंगी प्रकाशन की लागत प्रकाशक द्वारा वहन की जाएगी तथा इसकी पूर्ति उसके द्वारा विज्ञापनों से एकत्र की गई आय से की जाएगी । इस विषय में इंडियन एयरलाइंस की जिम्मेवारी होगी प्रत्येक अंक में केवल एक विज्ञापन की लागत का भार उठाना जो कि 2000 अमरीकी डालर के बराबर होगा, और इसके साथ इंडियन एयरलाइंस पत्रिका के लिए सामग्री एकत्र करने में जो कोई भी संभवत: सहायता दे सकेगी देगी । विज्ञापनों के लिए धन की अदायगी भारतीय रुपयों में की जाएगी ।

(घ) जी, नहीं ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण दिया जाना

174. **श्री निहाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की वित्तीय संस्थाएं छोटे और बड़े उद्योग-पतियों को उनका सामान गिरवी रख कर भारी मात्रा में ऋण प्रदान करता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार किसान द्वारा खाद्यान्नों आलू, प्याज, सरसों आदि को सरकारी बैंकों के गोदामों में जमा कराने पर, उसके लिए ऋण देने की व्यवस्था करने का है, ताकि मूल्य बढ़ने के समय उन्हें उचित भाव मिल सके तथा यह प्रबन्ध किस किस एजेंसी ने किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों को सहायता न प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). वाणिज्यिक बैंक, बंधक/माल/उत्पादन, मशीनरी आदि को दृष्टि बंधक रख कर कृषकों के साथ-साथ उद्योगों को भी ऋण मंजूर करते हैं । ये बैंक केन्द्रीय/राज्य मालगोदामों, ग्रामीण भण्डार गृहों आदि द्वारा जारी की गई गोदाम-रसीदों पर भी किसानों को ऋण स्वीकृत करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित भण्डारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण भण्डारगृहों की स्थापना की सरकारी योजना के परिणाम-स्वरूप इस सुविधा की और अधिक व्याप्ति होगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।